

## II. कुल मांग

2008-09 में कमजोर होती हुई कुल मांग वृद्धि के लिए एक बाधा के रूप में उभरी। वृद्धि में गिरावट को रोकने के लिए निजी खपत व्यय में काफी अधिक गिरावट और निवेश मांग में कमी को विस्तारपूर्ण राजकोषीय नीति की जरूरत पड़ी। इसलिए सरकारी खपत व्यय में तीसरी और चौथी तिमाही में तेजी से वृद्धि हुई तथा इसने 2008-09 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि (बाजार मूल्य पर) के 32.5 प्रतिशत का योगदान किया जबकि पिछले पांच वर्षों में इसका औसत अंशदान 5.9 प्रतिशत था। वृद्धि में गिरावट को रोकने के लिए 2009-10 के केन्द्रीय बजट में उच्च सरकारी व्यय की निरंतर प्रासंगिकता पर बल दिया गया है, जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बजट में किये गये उच्च राजकोषीय घाटे के प्रावधान में परिलक्षित होता है। कंपनी क्षेत्र के आंकड़े वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों के दौरान बिक्री वृद्धि में तीव्र गिरावट को दर्शाते हैं, करोत्तर लाभ में वृद्धि अंतिम तीन तिमाहियों में ऋणात्मक थीं। 2009-10 की पहली तिमाही की कंपनी निष्पादन की शीघ्र प्राप्त जानकारी पिछली तिमाही की तदनु रूप अवधि की बिक्री और लाभ में धनात्मक वृद्धि को दर्शाती है। निर्यात वृद्धि के सापेक्षिक आयात वृद्धि में तेजी से कमी के कारण 2008-09 की अंतिम तिमाही में निवल निर्यात घटा।

II.1 2003-08 की अवधि के दौरान भारत की वृद्धि में तेजी की कसौटी मजबूत और घरेलू मांग रही है। उच्च वृद्धि वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण 2008-09 में कम हुई। सही अर्थों में, 2008-09 के दौरान निजी खपत मांग में वृद्धि 2007-08 के 8.5 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 2.9 प्रतिशत हो गई; इस कमी के महत्व को जीडीपी में निजी उपभोक्ता मांग

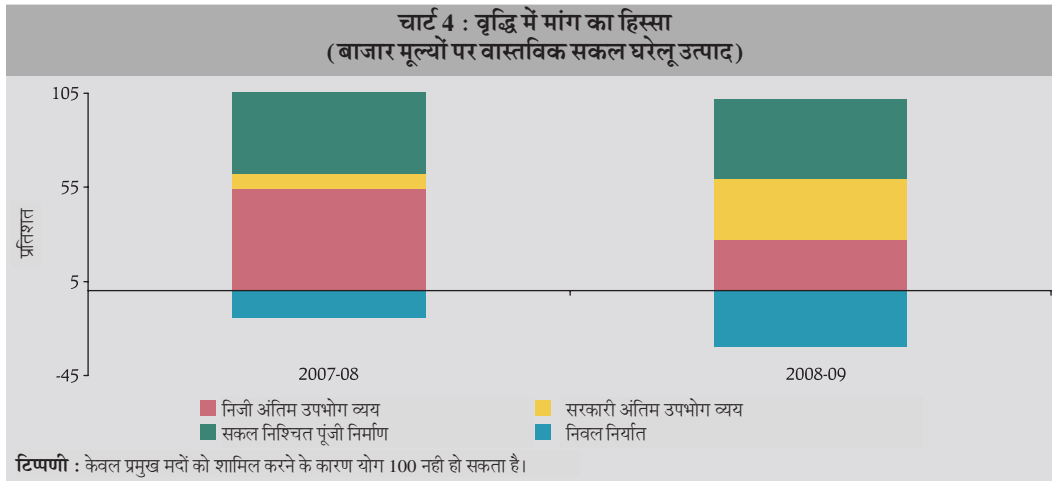
(2008-09 में 55.5 प्रतिशत) के अधिक अंश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। निवेश मांग, जिसका निश्चित सकल पूंजी निर्माण के व्यवहार से अनुमान लगाया जा सकता है, में भी कुछ गिरावट दिखाई। इसलिए, निजी खपत मांग में गिरावट के प्रतिसाद में आर्थिक वृद्धि में तीव्र कमी को रोकने के लिए सरकारी खपत व्यय में समंजनकारी विस्तार आवश्यक था। 2008-09 में सरकारी खपत व्यय 20.2 प्रतिशत बढ़ा, साथ ही वर्ष की तीसरी तिमाही में तीव्रतम वृद्धि हो रही थी। परिणाम के रूप में, 2008-09 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि (बाजार मूल्यों पर) में सरकारी खपत व्यय का योगदान 2007-08 के 8.0 प्रतिशत के विपरीत 32.5 प्रतिशत था। वृद्धि में गिरावट के प्रति राजकोषीय प्रतिसाद को दर्शाते हुए, केन्द्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात् राजस्व घाटा और 2008-09 के लिए संशोधित अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटा पूर्ववर्ती वर्षों की तरह अनुमानित स्तर से काफी अधिक था। चूंकि वर्तमान वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि कम बनी रही, 2009-10 के केन्द्रीय बजट में वर्ष के लिए और बड़े घाटों के लिए प्रावधान किया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, राजस्व घाटा सबसे अधिक होगा और सकल राजकोषीय घाटा 1993-94 से सबसे अधिक होगा। कंपनी निष्पादन मंद बना रहा, और मांग में कमी का प्रभाव 2008-09 की अंतिम तिमाही में बिक्री वृद्धि की काफी अधिक गिरावट में दिखा। लाभदायकता का प्रभाव प्रतिकूल था, विशेषरूप से तीसरी तिमाही के दौरान क्योंकि बिक्री में वृद्धि कम हुई। बाह्य मांग के संबंध में, अक्टूबर 2008 से निर्यात वृद्धि ऋणात्मक हो गई लेकिन आयात वृद्धि में और तेजी से गिरावट आई है। परिणाम के रूप में, निवल निर्यात (माल और सेवाओं का) 2008-09 की अंतिम

तिमाही में सुधरा। यह स्वरूप 2009-10 के पहले दो माहों में जारी प्रतीत होता है, जैसाकि वाणिज्यिक व्यापार शेष के व्यवहार से स्पष्ट है।

## घरेलू मांग

II.2 वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में, निवेशक और उपभोक्ता के विश्वास में क्षय अर्थव्यवस्था की प्रमुख मांग में आई कमी में परिलक्षित हुआ। खपत मांग, जो 2007-08 में मांग वृद्धि के सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में निवेश मांग से आगे निकल गयी थी, 2008-09 में जीडीपी वृद्धि की प्रमुख योगदानकर्ता बनी रही। 2008-09 में निजी अंतिम खपत व्यय की वृद्धि में तीव्र गिरावट के कारण, निजी खपत व्यय से सरकारी खपत व्यय में वृद्धि के योगदान में संघटनात्मक अंतर था। वास्तविक अर्थों में, जीडीपी वृद्धि में निजी खपत का योगदान, जो 2007-08 में 53.8 प्रतिशत था, 2008-09 में लगभग आधा घटकर 27.0 प्रतिशत हो गया, जबकि सरकारी खपत व्यय 2007-08 के 8.0 प्रतिशत के विपरीत 2008-09 में 32.5 प्रतिशत था (चार्ट 4)। इस प्रकार, निजी खपत और निवेश मांग में मंदी के प्रभाव को सरकारी अंतिम खपत व्यय, जिसे छोटे वेतन आयोग और प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय नीति उपायों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय से बल मिला, से समर्थन मिला।

II.3 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम निर्गम के अनुसार, निजी अंतिम खपत व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण में 2007-08 की तदनु रूप अवधि की तुलना में 2008-09 की चौथी तिमाही में कम वृद्धि जारी रही। सकल निश्चित पूंजी निर्माण की वृद्धि ने निजी उपभोग मांग में आई कमी को आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति



करना जारी रखा। परिणाम के रूप में, सरकारी अंतिम खपत व्यय का हिस्सा पिछली तिमाही की तदनु रूप अवधि की तुलना में चौथी तिमाही में बढ़ा जबकि निजी अंतिम खपत व्यय में गिरावट आई (सारणी 9)।

*संयुक्त रूप से बजट में प्रावधान किए गए वित्त: 2009-10*

II.4 2009-10 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बजटीय स्थिति बतलाती है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतकों के उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 10)। यद्यपि संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से कर राजस्व में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, संयुक्त कर - जीडीपी अनुपात 2008-09 की तुलना में 2009-10 में मामूली रूप से कम हुआ। व्यय पक्ष में, जबकि गैर विकासात्मक व्यय के काफी अधिक बढ़ने और जीडीपी में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, विकास व्यय के समग्र राशि के अर्थ में घटने का अनुमान लगाया गया है तथा परिणामस्वरूप कुल व्यय में और जीडीपी के अनुपात के रूप में इसका

हिस्सा 2008-09 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 2009-10 (बजट अनुमान) में कम होगा।

#### केन्द्र सरकार के वित्त

II.5 2009-10 के केन्द्रीय बजट, जो निरंतर वैश्विक आर्थिक मंदी और संबद्ध कम घरेलू मांग की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था, में उन राजकोषीय प्रोत्साहनों को बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया है जो मांग को आवश्यक प्रोत्साहन देने और इस प्रकार वृद्धि की संभावनाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए पिछले वर्ष शुरू किये गये। अगले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत वृद्धि की ओर लौटने के घोषित लक्ष्य को देखते हुए, बजट में की गयी घोषणाओं का उद्देश्य व्यय और कर रियायतों के आबंटन के समुचित मिश्रण के माध्यम से खपत मांग, निवेश मांग और घरेलू बचतों को बढ़ाना है। परिणाम के रूप में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात् राजस्व घाटे, समग्र राजकोषीय घाटे (जीएफडी) और सकल प्राथमिक घाटे (पीडी) के 2008-09 (संशोधित अनुमान) की तुलना में अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। जबकि राजस्व घाटा सबसे

सारणी 9 : बाजार मूल्यों पर जीडीपी का विन्यास (आधार : 1999-2000 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

मद	2007-08*	2008-09#	2007-08				2008-09			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>वृद्धि दरें</b>										
बाजार मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	9.1	6.1	9.2	8.8	9.4	8.8	8.2	7.8	4.8	4.1
कुल खपत व्यय	8.3	5.4	6.6	7.8	8.0	10.6	3.8	2.1	9.0	6.1
(i) निजी	8.5	2.9	8.4	7.5	8.9	9.0	4.5	2.1	2.3	2.7
(ii) सरकारी	7.4	20.2	-2.4	10.0	2.0	18.6	-0.2	2.2	56.6	21.5
सकल अचल पूंजी निर्माण	12.9	8.2	13.6	16.0	14.1	8.8	9.2	12.5	5.1	6.4
स्टॉक में परिवर्तन	51.7	2.9	54.1	51.7	52.2	49	6	5.6	1.4	-0.9
निर्यात	2.1	12.8	-4	-4.8	6.1	9.8	25.6	24.3	7.1	-0.8
घटाया: आयात	6.9	17.9	-0.7	-3.6	6.7	24.4	27.4	35.3	21.7	-5.7
<b>सापेक्ष हिस्सा</b>										
कुल खपत व्यय	66.9	66.5	70.4	67.3	67.2	63.6	67.5	63.7	69.9	64.8
(i) निजी	57.2	55.5	60	58.5	58.9	52.1	58.0	55.5	57.4	51.4
(ii) सरकारी	9.8	11.1	10.4	8.7	8.4	11.5	9.6	8.3	12.5	13.4
सकल अचल पूंजी निर्माण	31.6	32.2	31.9	33	30.8	31	32.2	34.5	30.9	31.6
स्टॉक में परिवर्तन	3.1	3.0	3.3	3.3	3.0	3.0	3.2	3.2	2.9	2.9
निवल निर्यात	-4.3	-5.8	-0.8	-7.0	-5.1	-4.3	-1.3	-10.5	-8.5	-2.9
<b>जापन : (करोड़ रुपए)</b>										
बाजार मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	34,02,716	36,09,425	7,70,241	7,88,041	9,01,966	9,42,467	8,33,630	8,49,247	9,45,121	9,81,427
* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान										
<b>टिप्पणी :</b> सारणी में सिर्फ प्रमुख मदों को शामिल करने के कारण आंकड़ों का योग 100 न हो ।										
<b>स्रोत :</b> केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन										

अधिक ऊंचे स्तर पर होगा, प्राथमिक घाटा सुधार अवधि के पश्चात भारत में सर्वाधिक होगा। राजस्व घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में अधिक वृद्धि के कारण होगी जो राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से अधिक होगी। पूंजी परिव्यय के भी काफी अधिक बढ़ने के कारण, 2008-09 में जीएफडी के संशोधित अनुमानों और अनंतिम खातों दोनों से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 10 और 11)।

II.6 जारी आर्थिक मंदी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित कटौती सकल कर राजस्व, जिसके

2008-09 के 11.8 प्रतिशत से 2009-10 के दौरान जीडीपी के 10.9 प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है, को प्रभावित कर सकती है। 2009-10 के दौरान राज्यों के समनुदेशन के निवल, केंद्र सरकार के कर राजस्व के जीडीपी के 8.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, गैर कर राजस्व - जीडीपी अनुपात के 2.4 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है (इसके विपरीत 2008-09 में जीडीपी के 1.8 प्रतिशत की गिरावट हुई थी), मुख्य रूप से थर्ड जनरेशन (3 जी) स्पेक्ट्रम की नीलामी से 35,000 करोड़ रुपए और रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं

**सारणी 10: प्रमुख राजकोषीय संकेतक**

(सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं*
1	2	3	4	5
<b>केंद्र</b>				
2007-08	-0.9	1.1	2.7	60.1
2008-09 सं.अ.	2.5	4.4	6.0	58.9
	(2.6)	(4.6)	(6.2)	
2009-10 ब.अ.	3.0	4.8	6.8	59.7
<b>राज्य</b>				
2007-08 #	-0.6	-0.9	1.3	25.8
2008-09 सं.अ.#	0.7	-0.2	2.5	25.2
2009-10 ब.अ.#	0.9	0.4	2.7	25.3
<b>संयुक्त</b>				
2007-08	-1.3	0.2	4.0	73.0
2008-09 सं.अ.	3.4	4.4	8.6	72.6
2009-10 ब.अ.	4.0	5.2	9.5	74.4

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

\* : ऐतिहासिक विनिमय दरों पर बाह्य देयताएं शामिल।

# : 2007-08 के आंकड़े 22 राज्य सरकारों से संबंधित हैं, जिनमेंसे 14 लेखा अनुदान हैं।

**टिप्पणी :** 1. ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े अनंतिम लेखों से संबंधित हैं।

से लाभांश/अधिशेष अंतरण में 28,600 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों (पिछले वर्ष की तुलना 58 प्रतिशत अधिक) के कारण।

II.7 2009-10 के कुल व्यय में अनुमानित वृद्धि पिछली वर्ष की तुलना में कम है, लेकिन उच्च आधार पर, नियोजित विस्तार का तात्पर्य पिछले वर्ष की तुलना में कुल मांग के लिए पर्याप्त अतिरिक्त प्रोत्साहन देना है। 2009-10 में कुल व्यय में निम्न वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में हल्की वृद्धि, विशेष रूप से उर्वरक सब्सिडी को नियंत्रित करने के माध्यम से होगी। 2009-10 में राजस्व व्यय की वृद्धि में योगदान करने वाली प्रमुख मदें ब्याज भुगतान, रक्षा और राज्यों को दिए जाने वाले गैर योजना अनुदान हैं, जिससे कुल मिलाकर राजस्व व्यय में 60 प्रतिशत से अधिक का इजाफा होगा। जबकि ब्याज भुगतान में वृद्धि सरकारी उधारों

में काफी अधिक बढ़ोतरी और 2008-09 के दौरान तेल विपणन कंपनियों तथा उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों में परिलक्षित होगी, रक्षा व्यय में वृद्धि वेतन और भत्तों तथा अनुरक्षण व्यय के लिए संवर्धित प्रावधानों के कारण होगी। ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों के लिए रक्षा व्यय के अनुपात को बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2009-10 के दौरान सब्सिडी में गिरावट होगी (चार्ट 5)। पूँजी व्यय में वृद्धि के 2008-09 की तुलना में 2009-10 में अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, मुख्य रूप से पूँजी परिव्यय (पूँजी व्यय- ऋण और अग्रिम) में अधिक वृद्धि के कारण, जिसमें 2008-09 के 22.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 33.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। रक्षा पूँजी परिव्यय, पूँजी परिव्यय में वृद्धि के लगभग आधे से अधिक होगा।

सारणी 11 : केंद्र सरकार का 2009-10 का अंतरिम बजट - एक नजर में

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	
				2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	5,41,864 (11.5)	5,62,173 (10.5)	6,14,497 (10.5)	3.7	9.3
i) कर राजस्व (निवल)	4,39,547 (9.3)	4,65,970 (8.6)	4,74,218 (8.1)	6.0	1.8
ii) करेतर राजस्व	1,02,317 (2.2)	96,203 (1.8)	1,40,279 (2.4)	-6.0	45.8
2. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	9,586 # (0.2)	12,265 (0.2)	5,345 (0.1)	27.9 #	-56.4
3. योजनेतर व्यय जिसमें से:	4,72,058 *	6,17,996 (11.6)	6,95,689 (11.9)	30.9 *	12.6
i) ब्याज भुगतान	1,71,030 (3.6)	1,92,694 (3.6)	2,25,511 (3.9)	12.7	17.0
ii) रक्षा व्यय**	91,681 (1.9)	1,14,600 (2.2)	1,41,703 (2.4)	25.0	23.7
iii) आर्थिक सहायता	70,926 (1.5)	1,29,243 (2.4)	1,11,276 (1.9)	82.2	-13.9
4. योजना व्यय	2,05,082 (4.3)	2,82,957 (5.3)	3,25,149 (5.6)	38.0	14.9
5. राजस्व व्यय	5,94,433 (12.6)	8,03,446 (15.0)	8,97,232 (15.3)	35.1	11.7
6. पूंजी व्यय	82,707 * (1.8)	97,507 (1.8)	1,23,606 (2.1)	17.9 *	26.8
7. कुल व्यय	6,77,140 * (14.3)	9,00,953 (16.9)	10,20,838 (17.4)	33.1 *	13.3
8. राजस्व घाटा	52,569 (1.1)	2,41,273 (4.4)	2,82,735 (4.8)	359.0	17.2
9. सकल राजकोषीय घाटा	1,25,690 * (2.7)	3,26,515 (6.0)	4,00,996 (6.8)	159.8 *	22.8
10. सकल प्राथमिक घाटा	-45,340 * (-0.9)	1,33,821 (2.5)	1,75,485 (3.0)	-395.1 *	31.1

\* : 2007-08 में भारतीय रिजर्व बैंक के स्टेट बैंक (एसबीआइ) के स्टेक के अधिग्रहण की लागत 35,531 करोड़ रुपए की निवल राशि।

# : स्टेट बैंक के स्टेक की बिक्री से प्राप्त 34,309 करोड़ रुपए के रिजर्व बैंक के अधिशेष की निवल राशि का भारत सरकार को अंतरण।

\*\* : इसमें राजस्व और पूंजी दोनों व्यय शामिल हैं।

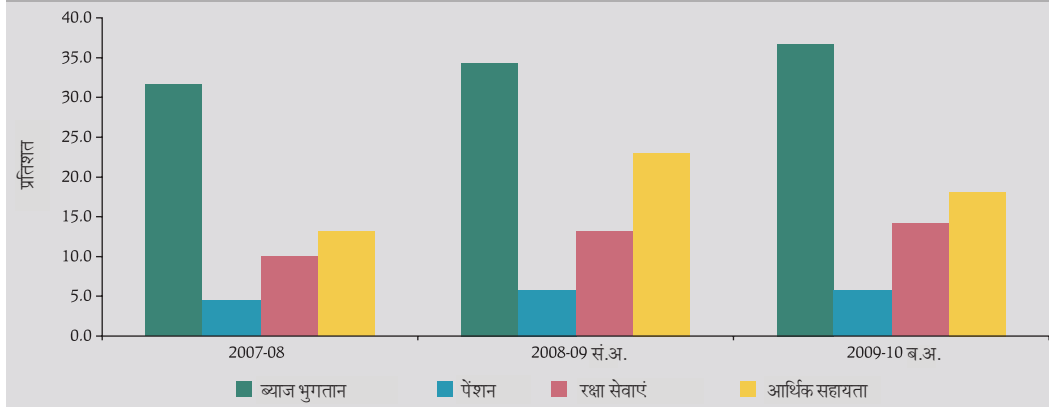
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

गैर- रक्षा पूंजी परिव्यय में वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत होगी। कुल व्यय में पूंजी व्यय 2008-09 (संशोधित अनुमान) के 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 12.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

केंद्र सरकार का वित्तीयन

II.8 बजट में प्रस्तावित के अनुसार जीएफडी के वित्तीयन स्वरूप से पता चलता है कि सरकार ने 2009-10 के दौरान घाटे की संपूर्ण राशि को बाजार उधारों के माध्यम से वित्तीयन करके पूरा करने की योजना बनाई है।

चार्ट 5 : राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में राजस्व व्यय की प्रमुख मंदा



बजट में नकद शेषों के आहरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसने 2008-09 में जीएफडी के 9.2 प्रतिशत का वित्तीयन किया था। 2009-10 के दौरान, जीएफडी वित्तीयन में बाह्य उधारों और लघु बचतों के विरुद्ध प्रतिभूतियों का हिस्सा 2008-09 की तुलना में अधिक रहेगा (सारणी 12)।

*अप्रैल-मई 2009 के दौरान केन्द्र की राजकोषीय स्थिति*

II.9 2009-10 (अप्रैल-मई 2009) के लिए केन्द्र सरकार की वित्त संबंधी उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में, राजस्व घाटे और जीएफडी को पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में काफी कम रखा गया है, जबकि समग्र राशि के अर्थ में वे अधिक थीं (सारणी 13)। बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में कम थे, जो आर्थिक मंदी और कर कटौती के प्रभाव को दर्शाते हैं। जबकि निगम कर और वैयक्तिक आय कर के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि अप्रैल-मई 2008 की तुलना में अप्रैल-मई 2009 के दौरान घटी, आबकारी और सीमा शुल्क के अंतर्गत संग्रहों में इसी अवधि में कमी आई। परिणाम के रूप में, गैर कर राजस्व में 48.0 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, राजस्व प्राप्तियां 2009

सारणी 12: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)		
मंद	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
1	2	3
सकल राजकोषीय घाटा	3,26,515	4,00,996
से पुनर्वित्त		
बाजार उधार	2,66,539 (81.6)	3,97,957 (99.2)
अल्प बचत के तहत जारी प्रतिभूतियां	1,323 (0.4)	13,256 (3.3)
बाह्य सहायता	9,603 (2.9)	16,047 (4.0)
राज्य भविष्य निधि	4,800 (1.5)	5,000 (1.2)
एनएसएसएफ	11,206 (3.4)	-103 (0.0)
आरक्षित निधि	-16,808 (-5.1)	-8,428 (-2.1)
जमा राशियां और अग्रिम	12,788 (3.9)	9,026 (2.3)
डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	2,594 (0.8)	2,672 (0.7)
नकदी आहरण	29,984 (9.2)	0 (0.0)
अन्य	4,486 (1.4)	-34,431 (-8.6)
<b>टिप्पणी</b> : कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में हैं।		

सारणी 13 : अप्रैल - मई 2009 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता				
मद	अप्रैल - मई (रुपए करोड़)		निम्न वर्षों के लिए बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में	
	2008	2009	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां	36,030	32,178	6.0	5.2
i) कर राजस्व (निवल)	31,958	26,152	6.3	5.5
ii) करेतर राजस्व	4,072	6,026	4.3	4.3
2. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	254	231	1.7	4.3
3. योजनेतर व्यय	71,496	86,242	14.1	12.4
जिसमें से:				
(i) ब्याज भुगतान	27,229	25,938	14.3	11.5
(ii) रक्षा	6,451	12,472	6.1	8.8
(iii) आर्थिक सहायता	18,002	25,131	27.1	22.5
4. योजना व्यय	37,989	36,925	15.6	11.4
5. कुल व्यय	1,09,485	1,23,167	14.6	12.1
6. राजस्व व्यय	1,03,761	1,13,141	15.8	12.6
7. पूंजी व्यय	5,724	10,026	6.2	8.1
8. राजस्व घाटा	67,731	80,963	122.7	28.6
9. राजकोषीय घाटा	73,201	90,758	54.9	22.6
10. सकल प्राथमिक घाटा	45,972	64,820	-79.9	36.9

स्रोत : महानियंत्रक लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

के पहले दो महीनों के दौरान 10.7 प्रतिशत तक घटी जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान इसमें 39.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अप्रैल-मई 2009 के दौरान, कुल व्यय (12.5 प्रतिशत पर) में वृद्धि अप्रैल-मई 2008 (20.6 प्रतिशत) की तुलना में कम थी, जिसमें वृद्धि में सापेक्षिक गिरावट राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में दिखी। जबकि अप्रैल-मई 2009 के दौरान गैर योजना व्यय में 20.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से व्यय, योजना व्यय के राजस्व घटक में 2.8 प्रतिशत (पिछले वर्ष 64.2 प्रतिशत) की कमी के कारण।

#### राज्य वित्त: 2009-10<sup>1</sup>

II.10 राज्य सरकारों के वित्तों के भी आर्थिक मंदी से प्रभावित होने की आशंका है, जो प्रमुख घाटा

<sup>1</sup> बाइस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित; जिसमें 14 लेखानुदान हैं।

संकेतकों में अनुमानित वृद्धि से स्पष्ट है। 2009-10 में राज्य सरकारों के समेकित राजस्व खाते के, राजस्व प्राप्तियों के संबंध में राजस्व व्यय में और अधिक अनुमानित वृद्धि के कारण, जीडीपी के 0.4 प्रतिशत के बराबर घाटे में रहने का अनुमान है जबकि पिछले तीन वर्षों में यह अधिशेष की स्थिति में रहा था। 2009-10 (बजट अनुमान) के दौरान राज्य सरकारों के राजस्व खाते में आई गिरावट कर राजस्व में देरी और प्रशासनिक सेवाओं पर अधिक व्यय जैसे कई राज्य सरकारों द्वारा छोटे वेतन आयोग के अवार्ड को लागू करने, पेंशन और ब्याज भुगतान के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। 2009-10 (बजट अनुमान) के दौरान, समेकित स्तर पर जीएफडी बढ़कर जीडीपी के 2.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2008-09 (संशोधित अनुमान) में यह जीडीपी का 2.5 प्रतिशत



था, मुख्य रूप से राजस्व खाते और उच्चतर निवल उधार देने की स्थिति के खराब होने के कारण।

### कंपनी निष्पादन

II.11 चुनिंदा गैर वित्तीय गैर सरकारी कंपनियों के निष्पादन के विश्लेषण से पता चला कि उनकी बिक्री वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में मामूली रूप से कम हुई। 2008-09 की पहली छमाही के दौरान बिक्री में भारी वृद्धि, जो आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि द्वारा समर्थित थी, वर्ष के बाद वाली छमाही में बुरी तरह से प्रभावित हुई, कमजोर उपभोक्ता मांग और मूल्यन शक्ति पर इसके प्रभाव के कारण। सकल लाभ - बिक्री अनुपात और करोत्तर लाभ - बिक्री अनुपात में मापित लाभ मार्जिन बड़े पैमाने पर पहली छमाही में उच्च निविष्ट लागत, विदेशी मुद्रा वाले

लेने-देनों पर मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) हानियों से संबंधित प्रावधान, ब्याज निर्गम में वृद्धि और घटती आय के कारण दबाव के अंतर्गत आ गये। फिर भी, ब्याज भुगतानों पर दबाव के कम होने (जिसमें वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में प्रत्येक में 50 प्रतिशत से अधिक की तुलना में मार्च 2009 को समाप्त तिमाही में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई), अन्य आय में वृद्धि, निविष्ट लागत में गिरावट (वस्तुओं के मूल्य में कमी को दर्शाते हुए) और दो वर्ष तक विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों से निपटने के लिए लेखांकन मानक (एएस 11) के कार्यान्वयन के स्थगन वे प्रमुख कारक थे जिन्होंने चौथी तिमाही में कुल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष कमी को घटाकर 19.9 प्रतिशत कर दिया जबकि तीसरी तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक तीव्र गिरावट हुई थी (सारणी 14)।

सारणी 14 : कंपनी क्षेत्र-वित्तीय कार्यनिष्पादन

(वृद्धि दरें / अनुपात प्रतिशत में)

मद	2007-08	2008-09	2007-08				2008-09			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिक्री	18.3	17.2	19.2	16.0	18.0	20.6	29.3	31.8	9.5	1.9
अन्य आय*	46.2	6.6	106.7	45.2	70.2	28.5	-8.4	-0.6	-4.8	39.4
व्यय	18.4	19.5	18.0	15.3	18.9	23.3	33.5	37.5	12.6	-0.5
मूल्यहास प्रावधान	14.8	17.4	18.1	15.8	17.9	15.4	15.3	16.5	16.8	19.6
सकल लाभ	22.8	-4.2	31.9	22.5	20.4	16.8	11.9	8.7	-26.7	-8.8
ब्याज भुगतान	28.8	57.3	4.4	18.4	45.7	35.8	58.1	85.3	62.9	36.5
करोत्तर लाभ	26.2	-18.4	33.9	22.7	29.4	14.1	6.9	-2.6	-53.4	-19.9
<b>चुनिंदा अनुपात</b>										
बिक्री के प्रति सकल लाभ	16.3	13.3	16.7	16.3	16.2	15.0	14.5	13.5	11.0	13.7
बिक्री के प्रति करोत्तर लाभ	11.8	8.1	11.6	11.5	12.2	10.3	9.7	8.6	5.3	8.1
बिक्री के प्रति ब्याज	2.2	3.1	2.0	2.1	2.5	2.2	2.4	2.9	3.8	3.2
सकल लाभ के प्रति ब्याज	13.8	23.6	11.8	12.8	15.3	14.6	16.8	21.5	34.6	23.3
ब्याज की व्याप्ति (वार)	7.3	4.2	8.5	7.8	6.5	6.8	6.0	4.6	2.9	4.3

\* : यदि स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए तो अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है।

**टिप्पणी :** 1. 2007-08 और 2008-09 के आंकड़े चुनिंदा गैर-सरकारी गैर वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की संक्षिप्त रिपोर्ट पर आधारित हैं।

2. वृद्धि दरें कंपनियों के कॉमन सेट के पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में संदर्भित अवधि के स्तर में हुए प्रतिशत बदलाव के रूप में हैं।

II.12 चुनिंदा गैर वित्तीय सरकारी (तेल और तेल से इतर) कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में राजस्व में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और उनके निवल लाभों में 11.4 प्रतिशत गिरावट आई। तेल से इतर कंपनियों के निवल लाभ में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान तेल कंपनियों के निवल लाभों में 26.4 प्रतिशत की गिरावट आई। इन कंपनियों के लाभ ब्याज भुगतानों के अत्यधिक निकास और अनुमानित वेतन पुनरीक्षण के लिए बड़े प्रावधानों के चलते स्टाफ की लागत में वृद्धि के कारण प्रभावित हुए। 2008-09 के दौरान, तीन तेल विपणन कंपनियों की कम वसूलियों के लिए उन्हें आंशिक तौर पर क्षतिपूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेल बांडों के निर्गम से वे 2008-09 में 4,260 करोड़ रुपए के संयुक्त निवल लाभ (2007-08 में 9,678 करोड़ रुपए के विपरीत) दर्ज कर सकीं।

### बाह्य मांग

II.13 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, निवल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं का) में परिलक्षित के अनुसार बाह्य मांग 2008-09 में घटकर (-) 6.0 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले वर्ष (-) 4.6 प्रतिशत थी। विश्व मांग में कमी ने भारत जैसे देशों के आयात को प्रभावित किया। वैश्विक आर्थिक संकट ने भी अंतरराष्ट्रीय तेल और उर्वरकों के मूल्य को कम किया। 2008-09 की

तीसरी तिमाही में आयात वृद्धि में गिरावट निर्यात वृद्धि की गिरावट की तुलना में तीव्रतर थी जिसमें तेल के कम मूल्य तेल के आयात को कम कर रहे थे और घरेलू मंदी तेल से इतर आयात को कम कर रही थी। इस प्रकार, वास्तविक जीडीपी में निवल निर्यात का हिस्सा दूसरी तिमाही के - 10.5 प्रतिशत से सुधरकर 2008-09 की अंतिम तिमाही - 2.9 प्रतिशत हो गया (देखें सारणी 9)। अप्रैल-मई 2009 के दौरान पण्य व्यापार घाटा 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो अप्रैल-मई 2008 के 19.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 48.7 प्रतिशत कम था, ऐसा इस अवधि के दौरान निर्यात की तुलना में आयात में सापेक्षिक रूप से व्यापक गिरावट के कारण था। बाह्य मांग की दशाओं पर एक विस्तृत चर्चा अध्याय III में की गयी है।

II.14 अंत में, 2008-09 के दौरान अर्थव्यवस्था में कुल मांग में आई गिरावट के प्रभाव को, निजी खपत मांग में तीव्र कमी और कम होती हुई निवेश मांग के कारण, वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी खपत व्यय में वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप से संमजित किया गया। 2009-10 के केन्द्रीय बजट में सरकारी व्यय के लिए व्यापक व्यवस्था की गयी और इसलिए व्यापक घाटे अर्थात् अर्थव्यवस्था में कुल मांग को समर्थन देना जारी रहेगा। 2009-10 में कंपनी क्षेत्र में मंदी बनी रही, जिसमें कम बिक्री वृद्धि और कर पश्चात लाभ में गिरावट शामिल थी।